

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 520]

मई विल्ली, बृहस्पतिबार, दिसम्बर 8, 1977 प्रग्रहायरा 17, 1899

No. 520]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 1977/AGRAHAYANA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिसते कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December 1977

S.O. 826(E).—In exercise of the powers conferred by section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby directs that all the powers exercisable by it under that Act and the rules made thereunder shall, in relation to the Cement Industry be exercised also by all the State Governments, subject to the condition that the Central Government shall continue to exercise all the powers under the said Act and Rules made thereunder—

- (i) relating to mines and quarries even where such mines and quarries form part of the Cement industry, and
- (ii) relating to the dispute between the employers who are members of the Cement Manufacturers Association, Express Building, Churchgate, Bombay and their workmen represented by Indian National Cement and Allied Workers' Federation, Mazdour Karyalaya, Congress House Bombay, which has been referred for arbitration in pursuance of section 10A of the said Act read with notification No SO 757-E dated 8th November, 1977 [No. S 11025/9/77/D I.(A)], in terms of the arbitration agreement published by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Order No L 20013/2/77/D O III(B), dated the 28th November, 1977

[No. S 11025/9/77/DI(A)]

D BANDYOPADHYAY, Jt Secy

श्रम मंत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1977

कां० थां० 826(भ्र),—केन्द्रीय सरकार, भ्रौद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उस अधिनियम भ्रौर उसके भ्रधीन बनाए गए नियमों के श्रधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां सीमेन्ट उद्योग के संबंध में सभी राज्य सरकारों द्वारा भी, इस शर्त के अधीन रहते हुए, प्रयुक्त की जाएंगी कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम भ्रौर उसके श्रधीन बनाए गए नियमों के श्रधीन सभी शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित के संबंध में करती रहेगी—

- (i) खानो भीर खदानों के संबंध में, वहां भी जहां ऐसी खानें भीर खदाने सीमेन्ट उद्योग का भग हो; भीर
- (ii) ऐसे नियोजको के, जो सीमेन्ट विनिर्माता संघ, एक्स्प्रेस भवन, चर्चगेट, मुम्बई के सदस्य है, श्रीर उनके कर्मकारों के, जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय सीमेन्ट श्रीर सहबद्ध कर्मकार परिसंघ, मजदूर कार्यालय, कांग्रेस हाउस, मुम्बई ने किया है, बीच विवाद के संबंध मे, जिसे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के श्रादेश सं० एल० 29013/2/77/डी० ग्रो० 3(बी), तारीख 28 नवम्बर, 1977 की श्रिधसूचना मे प्रकाशित माध्यस्थम् करार के निबन्धनों के अनुसार, ग्रिधिसूचना सं० का० श्रा० 757-श्र तारीख 8-11-1977 सिं० एस० 11025/9/77/डी० ग्राई० (ए)] के साथ पठित उक्त ग्रिधनियम की धारा 10क के अनुसरण में, माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

[सं० एस० 11025/9/77,डी०ग्राई० (ए)]

डी० बन्गोपाध्याय, सयुक्त सचिव ।